राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 97

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 15 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

बड़े मिशन के लिए होगा प्रयोगों का आगाज

>> 14

सरोकार

घर-आंगन में हो रही है पोषण की परवरिश

उत्तरकाशी : कुपोषण दूर करने में परिवार के सभी सदस्यों का जागरूक होना जरूरी है। इसकी बानगी पेश कर रहे हैं उत्तरकाशी जिले में भटवाड़ी ब्लॉक के 12 गांवों के दो सौ परिवार। ये सभी परिवार अपने घर-आंगन में पोषक तत्व युक्त सब्जियां उगाकर कुपोषण के खिलाफ जंग छेड़े हैं। (पेज-11)

रविवार विशेष

मुश्किलों को प्रतिभा का जोरदार मुक्का

कोलकाता : खिदिरपुर की तंग गलियों में गरीबी के बीच पली-बढ़ी एक लड़की। उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। लेकिन इसी संघर्ष ने उसे ऐसे तराशा कि वह गुमनामी से निकलकर विख्यात हो गई। यह कहानी किसी को भी प्रेरित करेगी। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

राह देखती रह गई सीबीआइ, हाजिर नहीं हुए राजीव कुमार

कोलकाता : नोटिस के बाद भी कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त और वर्तमान एडीजी (सीआइडी) राजीव कुमार पूछताछ के लिए सीबीआइ दफ्तर में हाजिर नहीं हुए। सीबीआइ की पांच सदस्यीय टीम करीब पांच घंटे तक उनका इंतजार किया। वहीं, राजीव कुमार ने सीबीआइ को ई-मेल भेजकर एक माह का समय मांगा है। गत शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सारधा चिटफंड मामले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी से रोक हटा दी थी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

चिन्मयानंद प्रकरण : एसआइटी को सौंपी पेन ड्राइव

शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा के पिता ने विशेष जांच दल (एसआइटी) को साक्ष्य सौंपे। बताया जा रहा है कि 64 जीबी की एक पेन ड्राइव दी गई है, जिसमें 43 वीडियो क्लिप हैं, जो चिन्मयानंद पर लगे आरोपों से संबंधित हैं। शनिवार को एसआइटी ने छात्रा की मां से पहली बार पूछताछ की। दोपहर ढाई बजे उन्हें पुलिस लाइंस स्थित अस्थाई कार्यालय बुलाया गया। साथ में छात्रा के पिता भी पहुंचे।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

मारा गया ओसामा का बेटा हमजा, ट्रंप ने की पुष्टि

वाशिंगटन : मीडिया में आई खबरों के करीब डेढ़ महीने बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अफगान-पाक सीमा पर अमेरिका के आतंकरोधी अभियान में हमजा मारा गया। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अल कायदा का प्रमुख आतंकी और ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन अफगान-पाक क्षेत्र में मारा गया।

नई चुनौती

टी-20 सीरीज
भारत vs द. अफ्रीका

शाम 7:00 बजे से
स्थान : धर्मशाला
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

एक्सपोर्ट और हाउसिंग को 70 हजार करोड़ का डोज

सहारे का हाथ ▶ इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए एक महीने के भीतर सरकार का तीसरा बड़ा एलान

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए हाल में किए गए उपायों की कड़ी में केंद्र सरकार ने शनिवार को निर्यात और हाउसिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का बड़ा पैकेज घोषित किया है। इसके तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष पहली जनवरी से एक नई स्कीम 'आरओडीटीईपी' शुरू करने और दुनियाभर में विख्यात दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर देश में चार 'मेगा शॉपिंग फेस्टिवल' आयोजित करने का फैसला किया गया है। अधूरे फ्लैट्स को शीघ्र पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का नया फंड बनाने का निर्णय भी किया गया है। केंद्र के इस कदम से एनसीआर सहित देशभर में लगभग 3.5 लाख फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। बीते एक महीने में यह तीसरा मौका है जब सरकार ने धीमी पड़ी विकास दर को तेज करने के लिए राहत उपाय घोषित किए हैं। सीतारमण ने जो भी कदम उठाए हैं उससे रोजगार को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट समेत अन्य को सीधा लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को निर्यात के लिए नई स्कीम 'रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑर टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट' (आरओडीटीईपी) सहित 12 सूत्री उपायों की घोषणा की। आरओडीटीईपी के तहत निर्यातकों को निर्यात पर चुकाए गए जीएसटी सहित सभी टैक्स से छूट मिलेगी। वित्त मंत्री का कहना है कि इस योजना के तहत निर्यातकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन से सरकार को लगभग 50,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी। आरओडीटीईपी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रावधानों के अनुकूल होगी और मौजूदा दो योजनाओं-एमईआइएस व पुरानी आरओएसएल का स्थान लेंगी, क्योंकि ये दोनों योजनाएं डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थीं। नई स्कीम के तहत निर्यातकों को मौजूदा योजनाओं की तुलना में अधिक फायदा होगा। हालांकि मौजूदा दोनों योजनाएं-एमईआइएस और आरओएसएल इस वर्ष 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी।

हाउसिंग क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए वित्त मंत्री ने तीन सूत्री उपायों की घोषणा की। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपये के एक विशेष फंड से उन निर्माणाधीन परियोजनाओं को वित्तीय मदद दी जाएगी, जो न तो एनपीए में तब्दील हुई हैं और न जिनका मामला एनसीएलटी में गया है। इस फंड में 10 हजार करोड़ रुपये सरकार मुहैया कराएगी। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अतानू चक्रवर्ती का कहना है कि एनसीआर सहित देशभर में लगभग 3.5 लाख ऐसे फ्लैट हैं जो इसके दायरे में आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संख्या घट-बढ़ सकती है। सरकार हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को नया मकान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी और हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को घटाकर सरकारी सिक्योरिटीज की 10 वर्षीय यील्ड से लिंक कर दिया जाएगा। आरबीआइ के साथ परामर्श कर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में ढील देने का फैसला भी किया है। इससे पहले वित्त मंत्री ने 23 अगस्त को 32 सूत्री उपायों और 30 अगस्त को बैंकों के विलय की घोषणा की थी। उस समय उन्होंने मकान खरीदारों के लिए उपाय करने का वादा किया था।

नई दिल्ली-नेशनल मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करती केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साथ में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर। जागरण

50,000 करोड़ रुपये का पैकेज एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लाई सरकार

20,000 करोड़ रुपये के फंड से मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग को दी जाएगी मदद

नई समस्या : फिक्स्ड रेट वाले होम लोन के बंद होने का खतरा पेज>>12

हाउसिंग के लिए ये कदम

- अधूरी पड़ी अफोर्डेबल और मिडिल इनकम कैटेगरी की हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष फंड बनाया जाएगा
- इस विशेष फंड में 10 हजार करोड़ रुपये सरकार देगी जबकि इतनी ही राशि एलआइसी और अन्य संस्थागत निवेशकों से जुटाई जाएगी
- इनसे उन निर्माणाधीन परियोजनाओं को वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी, जिन पर एनपीए या एनसीएलटी का साया नहीं है

एक्सपोर्ट के लिए ये कदम

- ड्यूटी और जीएसटी से मुक्ति, पोर्ट्स पर लगने वाला समय घटाने के लिए टेक्नोलॉजी से लैस करना
- एक्सपोर्ट्स के लिए वर्किंग कैपिटल मुहैया कराने वाले बैंकों को मिलेगा अब ज्यादा इंश्योरेंस कवर
- जीएसटी रिफंड की रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग

नियंत्रित है महंगाई दर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर भी तथ्य पेश किए। उन्होंने एक प्रजेंटेशन देते हुए कहा कि महंगाई नियंत्रित है और औद्योगिक उत्पादन की स्थिति सुधरने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस प्रजेंटेशन में विकास दर के आंकड़ों का जिक्र नहीं किया। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई को चार प्रतिशत से नीचे नियंत्रित रखा गया है। जीडीपी के अनुपात में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेट में भी वृद्धि हो रही है। औद्योगिक उत्पादन की स्थिति सुधरने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटे में भी कमी आई है। जीडीपी के अनुपात में चालू खाते के घाटे को भी नियंत्रित रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कुल दस ग्राफ दिखाए। हालांकि इसमें विकास दर में उतार-चढ़ाव दिखाने वाला ग्राफ शामिल नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि उनके प्रजेंटेशन में जीडीपी वृद्धि दर के बारे में कोई ग्राफ जान बूझकर शामिल नहीं किया या वह छूट गया तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि पांच प्रतिशत विकास दर का आंकड़ा ऐसा नहीं है कि जिसे वह नजरंदाज करें। उन्होंने साफ कहा कि कई क्षेत्रों की स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

सऊदी तेल कंपनी अरैमको के प्लांट पर ड्रोन हमला

सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी अरैमको के अबकैक स्थित संयंत्र पर ड्रोन हमले के बाद उठता धुआं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रायटर

- अबकैक और खुरैश स्थित संयंत्रों में लगी भीषण आग, ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी

रियाद, एजेंसियां : सऊदी अरब की नामचीन तेल कंपनी अरैमको के दो संयंत्रों को शनिवार को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। इससे अबकैक और खुरैश स्थित संयंत्रों में भीषण आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में शुमार सऊदी अरैमको के तेल प्लांट पर हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ईरान समर्थित यमन के हाउती विद्रोहियों ने ली है। इस हमले के चलते क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है।

पूर्वी सऊदी अरब में स्थित अरैमको के अबकैक और खुरैश फेसिलिटी सेंटर पर शनिवार तड़के करीब चार बजे ड्रोन से हमले किए गए थे। हमले के बाद दोनों संयंत्रों से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। सऊदी प्रेस एजेंसी ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया, 'ड्रोन हमले के चलते अरैमको के अबकैक और खुरैश फेसिलिटी सेंटर में लगी आग को बुझाने में कंपनी की औद्योगिक सुरक्षा टीमें तुरंत जुट गई थीं। दोनों जगहों पर आग पर काबू पाया जा चुका है।' मंत्रालय ने कहा कि देश के पूर्वी हिस्से में हुए ड्रोन हमले को लेकर यह जांच की जा रही है कि इसके पीछे किसका हाथ है?

दस ड्रोन से बनाया गया निशाना : हाउती समर्थित अल-मसिराह टीवी के अनुसार, अबकैक और खुरैश स्थित तेल संयंत्रों को निशाना बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया था। इसमें दस ड्रोन शामिल किए गए थे। हाउती विद्रोहियों ने यमन की सीमा से लगे सऊदी अरब में हाल के महीनों में हमले तेज कर दिए हैं। उसने पिछले माह भी अरैमको के एक नेचुरल गैस फेसिलिटी सेंटर पर हमला किया था। हाउती विद्रोहियों ने गत जून में सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया था। इसमें एक सऊदी नागरिक मारा गया था और 21 लोग घायल हुए थे। गत मई में हाउती विद्रोहियों ने सऊदी के दो ऑयल पंपिंग स्टेशन को भी निशाना बनाया था। ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों का यमन की राजधानी सना समेत देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना साल 2015 से ही इन विद्रोहियों से मुकाबला कर रही है।

उत्पादन और निर्यात प्रभावित : सूत्रों ने बताया कि ड्रोन हमले के बाद अरैमको के संयंत्रों में तेल उत्पादन और निर्यात प्रभावित हुआ है। हालांकि सऊदी के सरकारी टेलीविजन ने दावा किया है कि निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ा है। अधिकारियों ने अरैमको के संयंत्रों पर ड्रोन हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक चश्मदीद ने बताया कि उसे अबकैक में 15 एंबुलेंस और भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली।

पश्चिमी देशों के कर्मचारी भी : अरैमको में बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के कर्मचारी भी काम करते हैं। वे अबकैक में रहते हैं। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि हमले में उसके किसी नागरिक के घायल होने की खबर नहीं है।

शाह बोले- हिंदी से जुड़ेगा देश, विरोधी भड़के

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गृह मंत्री ने कहा- देश में एक भाषा अत्यंत आवश्यक, पासवान ने किया समर्थन
- तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक और विपक्षी दल द्रमुक ने चेताया

गृहमंत्री अमित शाह।

भारत में बहुत सी भाषाएं हैं और हर भाषा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि पूरे देश की एक भाषा हो जो वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बने।
- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

एक टैक्स, एक संविधान, एक राशन कार्ड के बाद अब हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाने पर सरकार आगे बढ़ेगी। हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भारतीय भाषाओं को तरजीह देते हुए कहा कि हिंदी भारत की पहचान बन सकती है। सभी को इसे इज्जत देनी चाहिए और सरकार भी यह कोशिश करेगी कि हिंदी हर घर तक पहुंचे। हालांकि हिंदी की यह वकालत दक्षिण के राज्यों को रास नहीं आई। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने जहां केंद्र को हिंदी थोपने के प्रति चेताया, वहीं विपक्षी दल द्रमुक ने शाह से बयान वापस लेने की मांग की। अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अमित शाह पर निशाना साधा।

शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि देश को एकता की डोर में बांधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वह सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा है। शाह ने तर्क दिया कि देश की विभिन्न भाषाएं और बोलियां हमारे देश की ताकत तो हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में देश को एक भाषा की जरूरत है ताकि यहां पर विदेशी भाषाओं को जगह न मिल सके। शाह ने याद दिलाया कि देश की एक भाषा को ध्यान में रखकर ही हमारे पुरखों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था।

शाह ने कहा कि हर किसी को अपनी मातृभाषा के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शाह के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा कि हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है जो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोती है और विश्व में हमारी पहचान भी है। भाजपा के सहयोगी दल लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शाह का समर्थन करते हुए कहा कि अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर उच्च अदालतों में भी हिंदी का प्रयोग शुरू होना चाहिए।

एक देश एक भाषा की यह वकालत दक्षिणी राज्यों और विपक्षी दलों को पसंद नहीं आई और वे शाह के बयान के बाद भड़क गए। अन्नाद्रमुक के नेता और तमिलनाडु के संस्कृति मंत्री के. पंडीराजन ने कहा, 'अगर केंद्र ने एकतरफा रूप से हिंदी थोपी तो न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी प्रतिक्रिया (विपरीत) होगी और समर्थन नहीं मिलेगा।' द्रमुक नेता एमके स्टालिन ने कहा, हम लगातार हिंदी को थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह की टिप्पणी से हमें आघात पहुंचा है, यह देश की एकता को प्रभावित करेगा। हम मांग करते हैं कि वह बयान वापस लें।

वाइको ने कहा, हिंदी के देश में केवल हिंदी भाषी राज्य होंगे पेज>>3

मेवात में हिंदू लड़की के निकाहनामे की जांच के आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : मेवात के एक प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग करना महंगा पड़ गया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े के निकाहनामे के जांच के आदेश जारी कर सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली। इस मामले में एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि वे दोनों अलग-अलग धर्म से हैं और उनके परिजन इस शादी से खुश नही हैं और उनकी जान को खतरा है इसलिए उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए।

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने बताया कि उनको याची द्वारा पेश किए तथ्य और निकाहनामे पर विश्वास नहीं हो रहा। आजकल उम्र और कई तरह की जानकारी को छुपाकर फर्जी तथ्यों के सहारे प्रेम विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा कि पेश किए गए निकाहनामे पर शक है।

पाक ने सफेद झंडा दिखाकर उठाए अपने दो सैनिकों के शव

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पाकिस्तानी सेना ने गुलमर्ग सब-सेक्टर के सामने हाजी पीर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए दो सैनिकों के शव शनिवार को सफेद झंडा लहराते हुए उठा लिए। हालांकि केरन सेक्टर में डेढ़ माह से पड़े सात शवों को पाक ने आज तक नहीं उठाया है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान की सेना ने गत 10 सितंबर को उड़ी सेक्टर के हाजी पीर दर्रे में स्थित भारतीय ठिकानों पर गोलाबारी की। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के एक दस्ते ने आगे बढ़ने का भी प्रयास किया। हालांकि भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सेना की निगरानी चौकी को उड़ा दिया और उसके दो सैनिकों को मार गिराया था।

शव उठाने के लिए लहराया सफेद झंडा : सैन्य सूत्रों के अनुसार, फायरिंग में पाक सेना का एक सिपाही गुलाम रसूल मारा गया। वह पंजाब प्रांत में बहावलपुर का रहने वाला था। उसका शव उठाने का प्रयास कर रहा एक अन्य पाकिस्तानी सैनिक भी मारा गया। वह भी पंजाब का ही था। भारतीय सेना की फायरिंग रेंज में होने के कारण पाक सेना इनके शव नहीं उठा पा रही थी।

शुक्रवार को पाक सेना ने भारतीय ठिकानों की तरफ संकेत करते हुए सफेद झंडा लहराया। इस झंडे का मतलब एक तरह से हथियार डालना है। इसके बाद भारतीय जवानों ने अपनी बंदूकें शांत रखीं और उन्हें शव ले जाने दिए। पाकिस्तान पिछले काफी समय से लगातार सीमा पर हालात बिगाड़ने में लगा है, लेकिन उसे हर बार भारत से कड़ा जवाब मिल रहा है।

जम्मू में पाक सेना की भारी गोलाबारी, स्कूलों के पास गिरे मोर्टार पेज>>5

जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य आधार

बेंगलुरु, प्रेट्र : जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने नए डीलर्स के वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने की बात कही है। इसे अगले वर्ष जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। यह कदम जीएसटी प्रक्रिया में धोखाधड़ी खत्म करने के लिए उठाया गया है। हालांकि जो डीलर आधार कार्ड नहीं देना चाहेंगे, उन्हें फिजिकल वेरीफिकेशन का मौका दिया जाएगा।

जीएसटीएन में मंत्रिसमूह के प्रमुख और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि जीएसटी वेरीफिकेशन में आधार को अनिवार्य कर दिया है, पहले यह वैकल्पिक था। पहले से रजिस्टर्ड डीलरों को भी आधार के जरिये वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। जीएसटी के तहत दर्ज कुछ डीलरों द्वारा फर्जी रसीद बनाए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। जीएसटीएन की ओर से कहा गया है कि वेरिफिकेशन के लिए आधार जमा करने के बाद तीन कार्यदिवस में डीलर को उसका जीएसटी नंबर प्रदान कर दिया जाएगा।

अहम मामला

चार नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में लगा है केस, जिसमें केंद्र सरकार को देना है जवाब। कोर्ट ने मई में सरकार से मांगी थी जानकारी, लेकिन सरकार दो बार बढ़ा चुकी है समय

समान नागरिक संहिता पर नवंबर में साफ हो सकती है स्थिति

माला दीक्षित, नई दिल्ली

'एक देश एक कानून' यानी समान नागरिक संहिता फिर चर्चा में है। संविधान में समान नागरिक संहिता लागू करने की स्पष्ट मंशा और उद्देश्य के बावजूद राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर पिछले 68 वर्षों से सरकारें सीधे तौर पर कोई कदम उठाने से बचती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस हालिया टिप्पणी कि इस मामले में सरकारों ने छह दशक से ज्यादा समय से कुछ नहीं किया, के बाद अब उम्मीद है कि चार नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार की ओर से स्थिति साफ की जाएगी। इस दिन सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग वाली याचिका पर अपना पक्ष रखेगी।

दिल्ली हाई कोर्ट में भाजपा प्रवक्ता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने गत 31 मई को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा था। आठ जुलाई को मामला सुनवाई पर लगा था लेकिन सरकार ने जवाब के लिए कोर्ट से समय मांग लिया था। इसके बाद 27 अगस्त को केस लगा और दूसरी बार भी सरकार ने समय मांग लिया। बदली परिस्थितियों में माना जा रहा है कि सरकार इस बार कोर्ट में अपना रुख साफ कर देगी। अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस के बाद अभिनव बेरी की ओर से भी एक नई याचिका इसी मुद्दे पर दाखिल की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उपाध्याय की याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट से उसे भी मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। समान नागरिक संहिता मूलतः सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में समानता लाने का मुद्दा है। इस पर संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में भी बड़ी बहस हुई थी। पहले इसे मौलिक अधिकारों में शामिल करने की बात थी। हालांकि समान राय नहीं बनने के बाद इसे नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। नीति निर्देशक तत्व लागू करना सरकार पर निर्भर करता है। सरकारों की ओर से आज तक सीधे तौर पर इसे लागू करने के कोई प्रयास नहीं हुए।

अभी देश में सभी धर्मों के विवाह और तलाक के कानून अलग-अलग हैं। साथ ही संपत्ति और पैतृकता के कानून भी अलग-अलग हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होना। सुप्रीम कोर्ट कई बार विभिन्न धर्मों के शादी, तलाक या गुजारा भत्ता के मुकदमों में समान नागरिक संहिता की वकालत कर चुका है। सबसे पहले 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात की थी। इसके बाद 1995 में सरला मुद्गल के मामले में और फिर 2003 में जान वेल्लामेटम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की तरफदारी की। अब एक बार फिर कोर्ट ने इसका पक्ष लिया है और अब तक सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ नहीं किए जाने पर भी टिप्पणी की है। गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है।

यूसीसी में छिपी है संविधान की मूल भावना पेज>>3

शीर्ष अदालत के रुख से उत्साहित भाजपा को तीनों अहम एजेंडे पूरे होने का भरोसा

नई दिल्ली : समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भाजपा को उत्साहित कर दिया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से नाराजगी जताई है कि आजादी के इतने साल बाद और संविधान की इच्छा के बावजूद देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं है। जाहिर है कि इस टिप्पणी के बाद भाजपा के लिए कदम बढ़ाना आसान होगा और इसका विरोध करते रहे दलों के लिए सीधा विरोध मुश्किल होगा। भाजपा और जनसंघ के एजेंडे में तीन सबसे बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसपर सहयोगी दलों के बीच भी विरोध और असमंजस रहा है। पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा इस कार्यकाल में तीनों मुद्दों के समाधान को लेकर आशान्वित है और वह भी संविधान के दायरे में। (पूरी खबर पेज तीन पर)

राई खेल यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर बने कपिल देव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने नियुक्ति के लिए किया नियमों में बदलाव

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को हरियाणा के राई स्थित खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति (चांसलर) नियुक्त किया गया है। राज्य के खेल मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। वर्ष 1983 में भारतीय टीम को पहला विश्व कप दिलाने वाले कपिल देव के कद को देखते हुए सरकार ने मानसून सत्र में ही नियमों में बदलाव कर यूनिवर्सिटी की कमान पूरी तरह उनके हाथों में सौंपने का रास्ता साफ कर दिया था।

नियमानुसार प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, लेकिन खेल विश्वविद्यालय को इस दायरे से बाहर रखा गया है। कपिल देव जहां यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे, वहीं राज्यपाल संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा कुलपति (वाइस चांसलर) की अलग से नियुक्ति की जाएगी। लगभग 630 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस यूनिवर्सिटी को प्रदेश सरकार जल्द शुरू करना चाहती है।

सोनीपत के राई में स्थित यह देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो किसी राज्य सरकार ने शुरू की है। इससे पहले गुजरात (स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी) और चेन्नई (तमिलनाडु फिजिकल एजेकुशेन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी) में खेल विवि संचालित हैं। कपिल ने 131 टेस्ट और 225 वनडे मैच खेले हैं। टेस्ट मैचों में कपिल देव ने 5248 रन और वनडे मैचों में 3783 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 434 विकेट और वनडे क्रिकेट में 253 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है।